ESTIMATES COMMITTEE

TWENTY-THIRD REPORT

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड) : अध्यक्ष महोदय, मैं १९५६-५७ के लिये एस्टिमेट समिति की रेल्वे बजट सम्बन्धी तेईसवी रिपोर्ट पेश करता हुं ।

COMMITTEE ON THE ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

THIRTEENTH REPORT

Shri Altekar (North Satara): I beg to present the Thirteenth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

I also lay on the Table a list showing names of Members who were continuously absent from the sittings of the House for 15 days or more during the Eleventh Session, 1955.

COMMITTEE ON PETITIONS

EIGHTH REPORT

Dr. Rama Rao (Kakinada): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Petitions.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION.—*Concld.*

Mr. Speaker: The House will now resume General Discussion on the General Budget. Out of 20 hours allotted for the general discussion, 17 hours and 40 minutes have been availed of till yesterday, the 15th March, 1956 and 2 hours and 20 minutes now remain.

How much time will the Finance Minister require to reply?

The Minister of Revenue and Civil Expenditure (Shri M. C. Shah): He will require 70 to 75 minutes to reply.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): If the Finance Minister is called upon to reply at say, 10 minutes to 2, he can go on till 3 o'clock. Non-official business may start at 3. If the time is extended by half an hour or 45 minutes, we should agree to it.

Mr. Speaker: So, we will go on with official business till 3 o'clock. We do not want any other official work after the Budget discussion. We have an hour more. The Finance Minister will start at 10 minutes to two. Non-official work will start at 3 o'clock.

Shri R. K. Gupta will continue his speech.

श्री आर० के० गुप्त (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कल कह रहा था, सब से बड़ी ज़रूरत आज यह है कि आमदनियों के अन्दर जो आज बड़ा भारी अन्तर है उस को कम किया जाय । इसके लिये मेरी तजवीज यह है कि जो बड़े बड़े अफ़सरों की तन्ख्वाहें हैं वह कम कर दी जायें । दस, पन्द्रह साल पहले जब हम गांवों में जाया करते थे तो कहा करते थे कि कांग्रेस राज्य की, जनता के राज्य की सबसे पहली बरकत यह होगी कि बड़े बड़े अफसरों की तन्ख्वाहें भी पांच सौ रुपये से ज्यादा नहीं होगी । मैं मानता हूं कि आजकल के हालात के मुताबिक पांच सौ रुपया बहुत कम है, लेकिन मेरी राय में दो हजार रुपये से ज्यादा किसी की भी तन्ख्वाह आज कल नहीं होनी चाहिए ।

इसी तरह से मेरी राय यह है कि फिल्म इन्डस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया जाय क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और वह इनकम चन्द बहुत बड़े बड़े आदमियों के हाथों में ही जाती है ।

मेरी यह भी राय है कि पेट्रोल को स्टेट ट्रेडिंग में ले लिया जाय और सीमेन्ट के प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया जाय । लेकिन खाली नेशनलाइजेशन से ही काम नहीं चलेगा । सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस नेशनलाइज्ड बिजिनेस को कंट्रोल कैसे किया जाय । पिछले दिनों एअरलाइन्स कारपोरेशन बनाया गया और उसको नेशनलाइज किया गया । लेकिन जिस रोज से उस का नेशनलाइजेशन हुआ है, उस में बराबर घाटा ही घाटा होता जा रहा है । इस लिये अगर इन तमाम नेशनलाइज्ड बिजिनेसों को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो उन में बहुत फायदा नहीं हो सकता ।